



अजमेर

Rashtradoot

फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 36

संख्या: 188

प्रभात

अजमेर, शुक्रवार 13 फरवरी, 2026

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

कायदे, कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी न होना भारी पड़ रहा है, भाजपा पर संसद में

जो हश्र “प्रिवलेज मोशन” का हुआ, वह ही अंजाम राहुल को डिस्क्वालिफाई करने के हल्ले का होगा?

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भाजपा और निशिकांत दुबे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालिफाई करने की मांग करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की धमकी दी थी। लेकिन यह धमकी इसलिए वापस ले ली गई, क्योंकि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति अभी तक गठित ही नहीं हुई है। संभव है कि रिजिजू को भी इस बात की जानकारी नहीं थी।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए एक तय प्रक्रिया और नियम होता है। पहले विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट देती है। इसके बाद मामला आचार समिति (एथिक्स कमेटी) के पास जाता है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसलिए प्लान बी के तौर पर निशिकांत दुबे को आगे किया गया।

- “प्रिवलेज मोशन” नहीं लाया गया, क्योंकि “प्रिवलेज कमेटी” का अभी तक गठन नहीं हुआ है। प्रिवलेज कमेटी प्रस्ताव का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देती है, जो “एथिक्स कमेटी” के सामने प्रस्तुत होती है। “एथिक्स कमेटी” की सिफारिश के बाद, निर्णय लिया जाता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ “प्रिवलेज मोशन” लाया जाए या नहीं। जब “प्रिवलेज कमेटी” का गठन ही नहीं हुआ अभी तक, तो “प्रिवलेज मोशन” की कार्यवाही आगे कैसे बढ़ती।
- इसी प्रकार निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को “डिस्क्वालिफाई” करने की मुहिम शुरू की। पर, यह स्पष्ट नहीं था कि राहुल गांधी को किस “रूल” के अंतर्गत “डिस्क्वालिफाई” करने की मांग की जा रही है या किस प्रक्रिया के जरिए राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है।
- निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतों की लाइन लगा दी, शून्यकाल में। पर, ये शिकायतें किसी भी “लैटर हैड” पर नहीं लिखी गई थीं तथा शिकायत पत्र पर किसी भी सांसद के हस्ताक्षर नहीं थे तथा यह भी स्पष्ट नहीं था कि यह शिकायत पत्र किस के पास भेजा जाए।

उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाए। लेकिन किस प्रस्ताव के तहत? किस नियम के तहत? किस प्रक्रिया के तहत? खुद सांसद को ही इसकी

जानकारी नहीं है। उन्होंने विपक्ष के नेता के खिलाफ शिकायतों की लंबी सूची लिखी और उसे शून्य काल में पढ़कर सुना दिया। जिस कागज पर शिकायत लिखी

गई, वह न तो कोई लेटरहेड था और न ही उस पर कोई हस्ताक्षर। यह शिकायत किसे संबोधित की गई थी? किसी को भी इसकी जानकारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सावलकोट पावर प्रोजैक्ट पर काम शुरू होने से घबराया पाकिस्तान

पाकिस्तान ने फिर से भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाया

-श्रीरंज झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत-पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल कम होता नज़र नहीं आ रहा है और आने वाले समय में भी इसके शांत होने की संभावना कम दिखती है।

पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर इस्लामाबाद के खिलाफ “पानी रोकने की नीति” अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं, भारत का कहना है कि उसे अपने क्षेत्र के अंदर बुनियादी ढांचा बनाने और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बेहतर प्रबंधन का पूरा संप्रभु अधिकार है।

पाकिस्तान की ताजा आपत्ति चिनाब नदी पर 5129 करोड़ रुपये की लागत वाली सावलकोट जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की खबरों के बाद सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत की

- भारत सरकार ने कहा, उसे अपने क्षेत्र में नदियों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
- इधर पाकिस्तान ने कहा कि उसकी पानी की तीन चौथाई जरूरत चिनाब जैसी नदियों से पूरी होती है, और भारत द्वारा बाँध बनाने से उसका पानी रुक जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने चिनाब पर 5129 करोड़ रूपए की लागत से सावलकोट पन बिजली योजना शुरू की है।

इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानूनी मंचों पर चुनौती देगा। पहलगाम हत्याकांड और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद भारत ने जम्मू-कश्मीर में कई जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया है और कहा है कि अपने बुनियादी ढांचे का प्रबंधन

करना उसका संप्रभु अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि देश के भीतर शुरू की गई किसी भी विकास परियोजना का फैसला हमारी अपनी समझ के आधार पर होता है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा सावलकोट बांध, सिंधु जल संधि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश चुनावों से गायब हैं महिला नेता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। बांग्लादेश के चुनावी परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया है। कभी शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी प्रभावशाली महिला नेताओं से पहचाने

- शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी सशक्त महिला नेताओं का नेतृत्व देख चुके बांग्लादेश के आम चुनावों में मात्र 4 प्रतिशत महिलाएं ही चुनाव मैदान में दिखीं।

जाने वाले देश में अब मतपत्रों पर महिलाएं लगभग नदारद हैं। देशभर में केवल 4 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं, जिनमें से कई केवल पुरुष नेताओं से जुड़ी प्रतीकात्मक उम्मीदवार मानी जा रही हैं।

जहां कुछ इस्लामी दलों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म “घूसखोर पंडित” का नाम बदलने का नोटिस दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म “घूसखोर पंडित” के निर्माताओं को इसके कथित जातिस्पृचक शीर्षक को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि “फिल्म का नया नाम बताइए, नहीं तो रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फिल्म का नाम ब्राह्मण भावनाओं को आहत करता है। कोर्ट ने कहा, इसे बदलें, वरना रिलीज की अनुमति नहीं मिलेगी।

“घूसखोर पंडित” नैटफिलक्स पर रिलीज की घोषणा के बाद विवादों में घिर गई है। आरोप है कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। अंग्रेजी में अनुवाद करने पर इस शीर्षक का मतलब एक भ्रष्ट ब्राह्मण होता है।

फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा

लोकसभा सचिवालय ने कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर जोर-शोर से शुरू हुए राजनीतिक ठकराव को हवा निकलती लग रही है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सक्रिय रूप से विचाराधीन नहीं है।

इस घटनाक्रम ने राजधानी में तीव्र राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है, विशेषकर ऐसी खबरों के बाद, कि स्पीकर कार्यालय ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से स्वयं को अलग कर लिया है।

विवाद की शुरुआत लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के तीखे भाषण के बाद हुई। अपने भाषण में, जिसमें आर्थिक आलोचना के साथ

हिंसा व हत्याओं के वातावरण में बांग्लादेश में चुनाव सम्पन्न

पिछले चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ

- अब शेख हसीना की पार्टी चुनाव क्षेत्र में नहीं है, अतः बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी आमने-सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं।
- भारत के लिए एक तरफ खड़ा और दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि दोनों ही भारत विरोधी पार्टियां हैं, तथा बांग्लादेश से हिंदुओं को बाहर निकालकर फैंकना चाहती हैं। अजीबोगरीब बात है, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जब हिंदू विरोधी हिंसा व वारदातें कम होती थीं। ये घटनाएं अब कई गुना बढ़ गई हैं।
- बहरहाल, बांग्लादेश में वर्तमान गरीबी व कानून व्यवस्था भारत के लिए भारी संकट पैदा कर रही है, क्योंकि इस निर्धनता व बेरोज़गारी के कारण भारत के लिए पलायन करने वाले बांग्लादेशियों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है और भारत के लिए संकट व सुरक्षा का मुद्दा और गंभीर बनाता जा रहा है।

से भी रोक दिया गया।

इसके बजाय, विभिन्न स्तरों की

कट्टरपंथी सोच वाले राजनीतिक दलों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बेअसर रहा भारत बंद

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। गुरुवार को सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा दिए गए भारत बंद के एक दिवसीय आ 1 न का सामान्य जनजीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा।

कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। राहुल गांधी और

- भारत बंद से अधिकांशतः जनजीवन सामान्य रहा, लेकिन तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व पंजाब में मिलाजुला असर दिखा।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यापार समझौते और श्रम कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि देश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘दूषित फल-सब्जियों की जांच के लिए 44 जिलों में मात्र 11 फूड सेफ्टी प्रयोगशालाएं ही क्यों हैं?’

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि हर जिले में फूड सेफ्टी लैब हो, ताकि लोगों को दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़े

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट व दूषित पानी में उगाई गई फल-सब्जियों से आमजन को होने वाली गंभीर बीमारियों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के 44 जिलों में मात्र 11 फूड सेफ्टी प्रयोगशालाएं ही क्यों हैं? राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश के हर जिले में एक प्रयोगशाला हो और वहां पर्याप्त प्रशिक्षित अधिकारी हों, जो नहरों व सिंचाई के अन्य स्त्रोतों की जांच करके यह सुनिश्चित करें कि गंदे पानी व दवाइयों अथवा रसायनों के उपयोग से फल-सब्जियों की पैदावार नहीं की जाए। हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया है। अदालत ने अलग-

अलग डेयरियों में दूध के सैंपल फेल होने के प्रकरण को भी गंभीरता से लेते हुए आरसीडीएफ को पक्षकार बनाने हुए जवाब तलब किया है कि दूध एकत्र करने के बाद प्लांट में पैकिंग तक, वह जांच की किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इसमें पूर्व महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी व उनके सहायक अधिवक्ता दर्श पारीक ने अदालत को बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर फल-सब्जियों को उगाने में फैक्ट्रियों तथा सीवरेज व गंदे नालों के दूषित पानी का उपयोग किया जाता है। न्यायमित्र सिंघवी ने कहा कि जयपुर के लोग चौमूं की सब्जियां पसंद करते हैं,

- अदालत ने आदेश दिए कि जिन नदी-नालों का पानी सिंचाई के काम में लिया जा रहा है, वहां एस.टी.पी. और आरओ प्लांट लगाया जाए।
- हाईकोर्ट ने प्रदेश में कई डेयरी ब्रॉंड्स के दूध सैंपल फेल होने पर चिंता जताते हुए आरसीडीएफ से मिलावट रोकने तथा जांच की प्रक्रिया के बारे में पूछा।

लेकिन सांगानेर की नहीं, क्योंकि सांगानेर की जमीन में फैक्ट्रियों का दूषित पानी जा रहा है और यहां पैदा होने वाली सब्जियां इससे दूषित हो गई हैं। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि कुछ समय पहले द्रव्यवती नदी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) बंद हो गए थे और उसी गंदे पानी से फल-सब्जियां उगाई जा रही हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए न तो उपयुक्त

संख्या में लैब है और न ही अधिकारी। इस पर महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि सांगानेर में एसटीपी संचालन करने वाली फर्म ने काम बीच में बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, वर्तमान में यह एसटीपी सुचारु रूप से चल रहा है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस.

सिंघवी ने अदालत को बताया कि प्रदेश में 44 जिले हैं, लेकिन मात्र 11 ही

टैस्टिंग लैब हैं, यानी 4 जिलों पर केवल एक लैब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपयुक्त अधिकारी भी नहीं हैं, जो नालों के पानी की जांच के लिए प्रशिक्षित हों। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि टैस्टिंग लैब में अधिकारी नियुक्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया अदालती आदेशों के कारण लंबित थी, परंतु राज्य सरकार ने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि नालों के पानी को ट्रीट करने के लिए एस.टी.पी. के साथ-साथ आरओ प्लांट भी लगाया जाए, परंतु प्रदेश के किसी भी जिले में एसटीपी के साथ आर.ओ. नहीं लगाया गया है।

खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए महाधिवक्ता से कहा कि 11 प्रयोगशालाओं से प्रदेश के सभी जिलों में कैसे काम चलेगा। आप यह अपेक्षा

करते हैं कि एक जिले का आदमी जांच के लिए दूसरे जिले में जाएगा। राज्य सरकार को देखना चाहिए कि हर जिले में प्रयोगशाला हो, वह लोगों के नजदीक हो, ताकि उसका उपयोग हो सके। इस पर एजी ने कहा कि यह प्रशासनिक निर्णय है। अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि जिन नालों का पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ-साथ आरओ प्लांट लगाया हुआ हो।

सोशल मीडिया पर मंदर डेयरी, अमूल और कंटी डिलिट्ट जैसे ब्रांड्स के दूध पैकेट्स के सैंपल जांच में फेल होने की जो खबरें चल रही हैं, वह मुद्दा भी सुनवाई के दौरान सामने आया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कक्षा-10 की परीक्षा का फॉर्मेट बदला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित प्रश्नपत्र पैटर्न से परिचित होने के लिए सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी

- सीबीएसई ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि नए फॉर्मेट को समझने के लिए सीबीएसई की वैंबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान व सामाजिक ज्ञान के नमूना प्रश्न पत्र को हल करें।

एजुकेशन (सीबीएसई) की शैक्षणिक वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के नमूना प्रश्नपत्रों का अध्ययन करें।

सीबीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड
Communications
Barat
India

भारत सरकार का उपक्रम
भारत SANCHAR NIGAM LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

संख्या-BSNLCO-11/12(11)/1/2025-RECTT-CO-Part (1)

दिनांक-03.02.2026

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) दूरसंचार-वित्त संवर्ग में निम्नलिखित कार्यकारी प्रशिक्षु (सीनियर एजीएनटीव ट्रेनी) के पद हेतु प्रत्यक्ष भर्ती योजना के अंतर्गत खुले बाजार से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी एवं नवीनतम अपडेट के लिए बीएसएनएल की वेबसाइट www.bsnl.co.in पर जा सकते हैं।

CBC 06204/12/0002/2526 बीएसएनएल निगम कार्यालय, नई दिल्ली

राज्य बजट 2026-27 में किसान कल्याण पर विशेष फोकस

राजस्थान में कृषि क्षेत्र के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में किसान कल्याण पर विशेष फोकस रखा है। बजट वर्ष 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड एक लाख 19 हजार 408 करोड़ 11 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 7.59 प्रतिशत अधिक है। सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से किसानों की आय, उत्पादकता और कृषि अवसरंचना को नई मजबूती मिलेगी तथा राजस्थान को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

बजट में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना के तहत 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन-फार्मिंग सेक्टर के लिए



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

590 करोड़ रुपये का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे करीब 26 हजार किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे।सिंचाई और खेतों की आधारभूत सुविधाओं के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्रस्तावित है। इसके तहत 8 हजार डिगियाँ, 15 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन तथा अगले दो वर्षों में 36 हजार फार्म पॉण्ड बनाए जाएंगे, जिससे 80 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

- रबी दलहनों का उत्पादन 22.34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 26.61 लाख मैट्रिक टन अनुमानित
- मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना में लक्ष्य के मुकाबले 99 प्रतिशत से अधिक गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित

50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 228 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सामुदायिक तारबंदी में न्यूनतम कृषक संख्या 10 से घटकर 7 कर दी गई है। इसके अलावा 50 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये का अनुदान तथा 500 कस्टम हार्वरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में उन्नत बीजों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख किसानों को मूंग, 1-1 लाख किसानों को मोठ और ज्वार-बाजरा-बरसीम के मिनीकित वितरित किए जाएंगे। 2.50 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। पांच हजार से अधिक आबादी वाली 3496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। प्रथम चरण में 2098 ग्राम पंचायतों में लगभग 270 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के तहत 'राज कृषि सूचना एवं प्रबंध प्रणाली' विकसित की जाएगी। एआई, एमएल, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से मौसम आधारित बुवाई, फसल स्वास्थ्य निगरानी और जोखिम प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 'मिशन राज गिफ्ट' भी

प्रारंभ किया जाएगा।

राजस्थान कॉर्पोरेट डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया गया है। 'सरस' ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए एनसीआर, यूपी और एमपी में आउटलेट्स खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 1.12 लाख किंवदंतल बीज वितरित किए गए। नई किस्मों के 31.50 लाख बीज मिनीकित निःशुल्क दिए गए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6,206 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 10.63 लाख पशु और 5.54 लाख परिवार लाभान्वित हुए। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन खरीदने पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया गया।

विधायक रोहित बोहरा ने किया अभद्र इशारा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा अभद्र इशारा करते हुए कैमरे में कैद हो गए। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों के लोकार्पण शिलान्यास का मुद्दा उठा रहे थे। रोहित बोहरा उनके पीछे बैठे थे।

इस दौरान बोहरा ने किसी विधायक को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, थोड़ी ही देर में उन्होंने हँसते हुए हाथ से अभद्र इशारा किया था। यह सब विधानसभा की लाइव फीड के कैमरों में भी कैद हो गया था। हालाँकि विधानसभा सदन में अब तक किसी विधायक ने इस पर चर्चा नहीं की थी। देर शाम सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।



भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा ने मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर “बजट राजस्थान 2026-27” के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया। कटारा ने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

दौसा तहसीलदार की कार्यशैली पर विधानसभा में हंगामा

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को दौसा तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने शून्यकाल के दौरान तहसीलदार पर मनमाणी और एससी वर्ग के लोगों के मकान तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार बचिव तबके के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है और उनका व्यवहार भी अत्यंत खराब है। बैरवा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल अपमानजनक है, बल्कि पूरे सदन के

- कांग्रेस विधायक बैरवा वेल में पहुँचे तो स्पीकर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया

लिए चिंताजनक है। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

मामले को लेकर सदन में माहौल उस समय गरमा गया जब विधायक बैरवा वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए इसे अनुशासनहीनता करार दिया। उन्होंने बैरवा को मर्यादा में रहने की हिदायत दी

फैक्ट्री से 1000 किलो साँस सीज

जयपुर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान खाद्य सुरक्षा एवं और स्वास्थ्य टीम टीम ने गुरुवार को मुहाना मंडी स्थित मैसर्स श्री श्याम फूड इंडस्ट्री पर कार्यवाही कर मिलावट के संदेह पर एक हजार किलो साँस सीज किया।

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि इस फैक्ट्री से उत्पादित श्री श्याम ब्रांड साँस का नमूना जांच रिपोर्ट में अनसफ पाया गया था। जिस पर टीम और रिसर्चलिंग के निर्देश पर टीम इस फैक्ट्री पर पहुँची। मौके पर टीम द्वारा स्नैक्स साँस और रेड चिली साँस के नमूने लेकर शेष एक हजार किलो साँस में कलर मिला होने एवं अन्य कोई मिलावट होने का संदेह होने पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक सीज किया गया। मौके पर फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, साँस, आचार आदि लगभग 150 किलो एस्पायर पाए गए। जिन्हें मौके पर नष्ट करवाया गया।

विधानसभा में फिर गुंजा खेजड़ी संरक्षण का मुद्दा

विधायकों ने गौशालाओं, विधायकों के सम्मान और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े प्रकरण भी उठाए

जयपुर (विसं)। राज्य विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान स्थान प्रस्ताव के जरिए विधायकों ने कई अहम मुद्दे उठाए। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने खेजड़ी के संरक्षण का मामला प्रमुखता से उठाते हुए इसे प्रदेश की लाइफ लाइन बताया। वहीं अन्य विधायकों ने गौशालाओं, विधायकों के सम्मान और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

हरीश चौधरी ने कहा कि खेजड़ी का अस्तित्व संकट में है और बीकानेर

सहित कई क्षेत्रों में इसके संरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में लाखों खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। हम सब इस मामले में विफल रहे हैं, लेकिन अब मिलकर इसे रोकना होगा, उन्होंने कहा। चौधरी ने बताया कि टेनेसी एक्ट लागू होने के समय खेजड़ी एक प्रकार की संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन आज यह प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है।

चौधरी ने चर्चा के दौरान एक समाज विशेष का उल्लेख किया, जिस

पर विधायक पटेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि उनका नाम लिया जा रहा है तो उन्हें पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।

इस बात को लेकर दोनों विधायकों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करते हुए चौधरी को अध्यक्ष को संबोधित करने के निर्देश दिए। टोका-टाकी के बीच चौधरी ने कहा कि आवश्यकता होगी तो वे नोटिस देकर भी बात करेंगे, लेकिन खेजड़ी का संरक्षण अत्यंत जरूरी है।

17 फरवरी को बजट बहस का जवाब देंगी सरकार

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कार्य सलाहकार समिति (बीएससी) ने 19 फरवरी तक का विस्तृत कामकाज तय कर दिया है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में बीएससी का प्रतिवेदन पेश करते हुए आगामी दिनों की कार्यवाही की रूपरेखा साझा की।

बीएससी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 12, 13, 16 और 17 फरवरी को राज्य बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। इन चार दिनों के दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट के विभिन्न प्रावधानों, घोषणाओं और वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बात रखेंगे।

बजट को लेकर पहले ही सदन में तीखी बहस के संकेत मिल चुके हैं और आने वाले दिनों में यह चर्चा और तेज होने की संभावना है। आगामी 14 और 15 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही अवकाश के कारण स्थगित रहेगी। इसके बाद 17 फरवरी को डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। माना जा रहा है कि वे विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों-कर्म, घोषणाओं के क्रियाव्यवस्था, सामाजिक योजनाओं और किसानों से जुड़े विषयों-पर सरकार का पक्ष विस्तार से रखेंगी।

‘नेता प्रतिपक्ष को फॉर्च्यूनर मिलने से हुई डोटासरा को तकलीफ’

भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने सदन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर कटाक्ष किया

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान भाजपा विधायक कैलाश वर्मा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्रियों के लिए वाहन हर सरकार में खरीदे जाते हैं, इसमें मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर ली गई तो डोटासरा को तकलीफ हो गई। यही फॉर्च्यूनर

मंत्रियों के साथ नेता प्रतिपक्ष को भी मिली है। मुझे लगता है उन्हें इस बात से ज्यादा परेशानी है कि नेता प्रतिपक्ष को यह सुविधा कैसे मिल गई।

इस टिप्पणी पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। हंगामे के बीच कैलाश वर्मा ने आपत्ति करने वाले विधायकों से कहा, मुझे क्या बोलना है, यह आप तय नहीं करेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। विपक्ष

के विरोध के कारण सदन में कुछ देर तक शोर-शराबा रहा, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।

बजट पर चर्चा के दौरान कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश को विरासत में कर्म का बड़ा बोझ देकर गई है और वित्तीय स्थिति को बिगाड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर किया।

6 करोड़ रुपए के गांजा तस्करी करने वाले को राहत नहीं

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंकाक से करीब छह करोड़ रुपए के हाईड्रोपोनिक वीड (गांजा) की तस्करी के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश इज्जतुल कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने साधारण गांजा नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और कई गुणा नशीला हाईड्रोपोनिक वीड की तस्करी की है। ऐसे मादक पदार्थ युवाओं को नशे का आदि बना रहे हैं।

भजनलाल सरकार का तीसरा बजट “विकसित राजस्थान” का रोडमैप : डॉ. प्रेमचंद बैरवा



उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की।

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को विकसित राजस्थान का रोडमैप बताया।

बीजेपी ऑफिस में प्रेस वार्ता में डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत 6.10 लाख करोड़ रुपये का बजट, वर्ष

2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है।

अवसरंचना विकास के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 32 हजार 526 करोड़ (53 प्रतिशत वृद्धि), शिक्षा क्षेत्र में 69 हजार करोड़ (35 प्रतिशत वृद्धि), कृषि बजट में 7.59 प्रतिशत और ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान

किया गया है। 400 विद्यालयों को सीएम राज्ज विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा तथा राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है।

युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1 लाख पदों का भी कैंडलैड जारी किया गया है।

किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण और 800

करोड़ ब्याज अनुदान का प्रावधान है। शेखावाटी तक यमुना जल लाने के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी।

जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के अनुरूप 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आधार स्तंभ साबित होगा।

डीजीपी राजीव शर्मा ने ली पुलिस और पर्यटन विभाग की बैठक



पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने गुरुवार को पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की।

जयपुर। राजस्थान आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजामों के लिए गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पुलिस व पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। डीजीपी ने प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पर्यटन स्थलों पर स्थापित पर्यटक सहायता बल (टीएएफ) को और सुदृढ़ करने, पर्यटन थांनों की संख्या बढ़ाने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित पुलिस बल लगाने और इन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने हाल ही में पर्यटन विकास के लिए बजट में दी गई स्वीकृति पर कार्ययोजना तैयार करने व पर्यटन स्थलों पर विशेष त्योहारों, मेलों के साथ-साथ सामयिक आयोजनों में भी पर्यटन विभाग की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य भर के विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलों या खादू श्यामजी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, रामदेवरा, गोमामेड़ी, पुष्करजी, श्रीनाथद्वारा, सांवरियाजी आदि में कुशल प्रबंधन के लिए देवस्थान, पुलिस व प्रशासन मिलकर कार्य करें और पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्थाएं करें।

बैठक में डीजी (ट्रेफिक) अनिल पालीवाल ने पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए की

जाने वाली व्यवस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न दूतावासों से संपर्क कर पर्यटन आमंत्रण की बात कही। आईजी अजयपाल लांबा ने डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों को नियोजित करने, एक ही स्थान पर समस्त सरकारी कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पर्यटन स्थलों पर अधिकारधिक सीसीटीवी कवरेज करने, पांच डेस्टिनेशन जहां सबसे ज्यादा ट्यूरिस्ट आते हैं वहां पर्यटन थांना बनाने, ट्यूरिज्म के नेशनल पोर्टल पर राज्य के पोर्टल को लिंक करने आदि के सुझावों की जानकारी दी। बैठक में पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड ने पर्यटन स्थलों की वर्तमान स्थिति और वहां पर विभाग द्वारा पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री, बुथ डिजाइन, प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में जानकारी दी।

खादूश्यामजी मेले में विशेष प्रबंध करें

डीजीपी शर्मा ने खादूश्यामजी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पर्यटन पुलिस और टीएएफ की ओर से विशेष प्रबंध किए जावें।

उन्होंने पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह-जगह पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए नियंत्रण कक्ष नंबर, पुलिस हेल्पलाइन 112, राजकाप सिटीजन एप आदि के लिंक इत्यादि दर्शाती हुई स्टैंडीज व टीएएफ की ओर से विशेष सहायता बृथ स्थापित करने के निर्देश दिए और कहा कि टीएएफ की उपस्थिति दिखनी चाहिए।

पर्यटकों को मिले बेहतर सुविधाएं : डीजीपी ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप अमेर की केस स्टडी में आई अपेक्षाओं को समस्त पर्यटक स्थलों पर लागू करने की बात कही। उन्होंने सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के साथ-साथ पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण और आवागमन के लिए व्यवस्थित सड़क सुविधा के साथ-साथ पर्यटकों के लिए अपेक्षित सूचनाओं की उपलब्धता के संबंध में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों के साथ-साथ रेल्वे स्टेशन, हवाई अड्डा और अन्य स्थानों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक सहायता बृथ स्थापित हो जहां पर पर्यटक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संपर्क कर सकें। बैठक में एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) वी.के.सिंह, एडीजी (ट्रेफिक) बीएल मीणा सहित पर्यटन, आरटीडीसी,आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम और संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

‘‘राइट टू हैल्थ’’ एक्ट पर विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष में घमासान

सरकार का कहना था कि मौजूदा योजनाओं में स्वास्थ्य का अधिकार मिल रहा है, अलग कानून की जरूरत नहीं

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2०22 (राइट टू हेल्थ) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार हंगामा देखने को मिला। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

विधायक हरिमोहन शर्मा ने, अप्रैल 2०23 में अधिसूचित राइट टू हेल्थ एक्ट के नियम अब तक लागू नहीं किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि नियम क्यों नहीं बनाए गए, प्राप्त सुझावों पर क्या निर्णय हुआ और इस संबंध में हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है? साथ ही, उन्होंने हाईकोर्ट के नोटिस

- कांग्रेस का कहना था कि नियम नहीं बना कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया।

और सरकार के जवाब की जानकारी भी मांगी।

इस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवरसर ने कहा कि पिछली सरकार चुनाव से ठीक पहले बिना पर्याप्त तैयारी के यह अधिनियम लेकर आई थी। नियम नहीं बनाए गए और हितधारकों से समुचित चर्चा भी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अधिनियम के नियमों को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल लंबित है और निर्णय प्रतीक्षित है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही “मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना” के तहत 25 लाख रुपये तक का वार्षिक कैशलेस इलाज उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है और 217.9 उपचार पैकेज इसमें शामिल हैं। निःशुल्क जांच, दवाइयां, ओपीडी, आर्थोपीडी, आपातकालीन सेवाएं, हीमोडायलिसिस और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं पहले से दी जा रही है।

ऐसे में अलग से इस एक्ट की आवश्यकता नहीं है।

मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष ने सीधा सवाल किया कि सरकार राइट टू हेल्थ लागू करना चाहती है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नियम नहीं बनाकर जनता के स्वास्थ्य अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी और चेतावनी दी कि स्थिति नहीं संभली तो सदन स्थगित करना पड़ेगा। अंततः विपक्ष ने विरोधस्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बता दिया है कि फिल्म का नाम बदला जा रहा है और टेलर तथा प्रचार सामग्री पहले ही वापस ले ली गई है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं से यह भी बताने को कहा कि क्या फिल्म “घूसखोर पंडित” में किसी समुदाय के प्रति आपत्तिजनक सामग्री दिखाई गई है।
कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से इस संबंध में हलफनामा भी मांगा है।
अदालत ने, “फ्राईडे फिल्मवक्स” द्वारा निर्मित इस फिल्म की टीम को फटकार लगाते हुए पूछा कि फिल्म निर्माता संयम क्यों नहीं बरत सकते।

बेअसर रहा भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
की सभी ट्रेड यूनियनं, किसान और मजदूर मोदी सरकार के व्यापार समझौते, श्रम कानूनों और मनरेगा को समाप्त करने के खिलाफ सड़कों पर हैं।
ओडिशा, केरल, तमिलनाडू, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित, कई राज्यों में मिला-जुला असर देखने को मिला।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजदूरों और किसानों के भविष्य से जुड़े निर्णय लेते समय उनकी

आवाजों को नज़रअंदाज़ किया।
केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों ने आज दिनभर की हड़ताल कर केन्द्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कार्रगोरेट समर्थक नीतियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। मंच ने दावा किया कि नई श्रम संहिताओं सहित, अन्य मुद्दों के विरोध में सामान्य हड़ताल के लिए 3० करोड़ मजदूरों को संगठित किया जा रहा है।

सावलकोट पावर प्रोजैक्ट पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के स्थान के बाद केन्द्र सरकार से मंजूरी पाने वाली पहली बड़ी नई परियोजना है। इसके अलावा, पाकल डुल, किरू और रतले बांध परियोजनाओं की भी शुरु करने की प्रक्रिया चल रही है।
भारत सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से पानी के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन होगा और देश की बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

पाकिस्तान भारत की इन कार्रवाइयों का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि भारत द्वारा बांध बनाने से

कायदे, कानून व प्रक्रिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसे फर्जी ही कहा जा सकता है।

लेकिन सरकार की हर बात को दोहराने वाला सुविधाजनक गोदी मीडिया यह खबर चला रहा है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। यह बात निश्चित रूप से हर उस भाजपा समर्थक के दिल और दिमाग में

- ‘‘डिस्क्वालिफिकेशन’’ करने के लिए कायदे-कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी कान होना, फिर कार्रबा बना, राहुल गांधी को ‘‘डिस्क्वालिफाई’’ करने के प्रयास के असफल होने का।

हो सकता है जो राहुल गांधी से नफरत करता है, और ऐसे लोग काफी संख्या में हैं। लेकिन बिना सही नियम और

प्रक्रिया के यह सपना हकीकत कैसे बनेगा? यही वह मुख्य सवाल है, जिसे पूछा जाना चाहिए।

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
था कि गांधी के बयानों से संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हुई है और इससे सशस्त्र बलों का मनोबल प्रभावित हो सकता है, और संसदीय संदर्भ में यह एक गंभीर आरोप है।

लेकिन शाम तक परिदृश्य बदलता दिखाई दिया। संसदीय सूत्रों ने संकेत दिया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने, या अयोग्यता से संबंधित किसी प्रस्ताव को संस्थानत समर्थन नहीं मिला। संसदीय कार्यसूची में किसी औपचारिक उल्लेख का न होना इस बात का संकेत था कि इस कदम पर पुनर्विचार किया गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्संतुलन है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली होने के बावजूद, भाजपा के पास वर्तमान लोकसभा में ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं है कि विपक्ष के नेता के खिलाफ विवादस्पद अनुशासनात्मक कार्रवाई आसानी से की जा सके। ऐसे किसी भी कदम के लिए, सदन प्रबंधन, सहयोगियों के साथ समन्वय और,

सबसे ऊपर, संभावित प्रतिक्रिया का राजनीतिक आकलन आवश्यक होता। एनडीए के व्यापक दायरे के सूत्रों के अनुसार, टीडीपी और जेडी (यू) जैसे प्रमुख सहयोगी दल ऐसे बड़े टकराव से असहज हो सकते हैं, क्योंकि इसे असहमित दबाने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगामी महत्वपूर्ण राज्य विधानसभाओं चुनावों को देखते हुए, गठबंधन का गणित, वैचारिक स्थिति जितना ही महत्वपूर्ण है।

राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी अतिशयता पूर्ण कार्रवाई से विपक्ष को एकजुट होने का अवसर मिल सकता था और इस कार्रवाई से गांधी की राष्ट्रीय छवि के और मजबूत हो जाने की सम्भावना थी।

इसके अतिरिक्त, इस पूरी महत्त्वपूर्ण चर्चा-प्रबंधन का पहलू भी गहनतर्पुर्ण है। किसी भाषण के हिस्सों को हटाना अध्यक्ष का एक प्रक्रियात्मक अधिकार है, लेकिन जब यह कदम विवादस्पद राजनीतिक आरोपों से जुड़ता है, तो कभी-कभी वही बात और अधिक फैल जाती है, जिसे निर्यांत्रित

करने की कोशिश की जाती है। डिजिटल युग में, अभिलेखों से हटाए गए अंश अक्सर आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर व्यापक रूप से प्रसारित हो जाते हैं, जिससे संसर्गश्रिफ्त का व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो जाता है और राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय जांचों से जुड़े संभावित भविष्य के खुलासों से सम्बन्धित अटकलों ने राजनीतिक माहौल में अनिश्चितता का तत्व जोड़ दिया है। यद्यपि शीर्ष भारतीय नेतृत्व को फंसाने वाले किसी संभावित खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी रिपोर्टों का प्रसार ही राजनीतिक हलकों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे माहौल में संसदीय टकराव को बढ़ाना अनिश्चित परिणामों वाला दुःसाहस माना जा सकता था।

मोदी सरकार के सामने दृढ़ता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। बिना किसी न्यायिक दोषसिद्धि या स्पष्ट संवैधानिक आधार के, नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता समाप्त

करने के सीधे प्रयास को न केवल प्रक्रियात्मक और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने के विपक्षी दलों के आरोपों को भी बल मिल सकता था।

राहुल गांधी के लिए यह प्रकरण उनके विकसित होते संसदीय व्यक्तित्व को रेखांकित करता है, एक ऐसे नेता के रूप में, जो तीखे टकराव से पीछे नहीं हटता। यह रणनीति उन्हें दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ देगी या नहीं, यह अभी देखना बाकी है। फिलहाल, जो विशेषाधिकार प्रस्ताव आसप्त प्रतीत हो रहा था, वह राजनीतिक दांव-पेंच और संसदीय व्यावहारिकता के टकराव का उदाहरण बन गया है।

निष्कर्षतः, यह प्रकरण समकालीन भारतीय राजनीति की इस व्यापक सच्चाई को उजागर करता है कि लड़ाइयाँ केवल सदन के पटल पर ही नहीं, बल्कि धारणा, गठबंधन प्रबंधन और चुनावी गणित के क्षेत्र में भी लड़ी जाती हैं और कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण कदम वही होता है, जो अंततः उठाया ही नहीं जाता।

मोदी आज नए ऑफिस ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होंगे

नई दिल्ली, 12 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होंगे। जानकारी के अनुसार, मोदी दोपहर करीब 1:3० बजे ‘सेवा तीर्थ’

- सेवा तीर्थ के साथ ही कर्तव्य भवन-1 और 2 का भी शाम 6 बजे उद्घाटन होगा।

बिल्डिंग कॉम्पलेक्स के नाम का अनावरण करेंगे।फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद, पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन-1 और 2 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में हैं।

‘ दिल्ली हवा खाने नहीं आए हैं, राजनीति करने आए हैं’

कर्नाटक के नेता शिवकुमार ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए टिप्पणी की

- डी के शिवकुमार ने खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका से मुलाकात की।

- शिवकुमार की इस मीटिंग के बाद एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरु हो गई है।

हालांकि शिवकुमार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा से मुलाकात पर सीधा जवाब नहीं दिया। शिवकुमार की इस मुलाकात के बाद कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही है।

‘दूषित फल-सब्जियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि डेयरियों में पहुंचा हुआ दूध मिलावटी नहीं है। इस दौरान पूर्व महाधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि पशुओं को ऑक्सिटीसीन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे दूध उत्पादन

तालेड़ा के स्कूल में स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका पर हमला किया

बालिका के दादा के अनुसार, उसके चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर पर घाव हैं

- कोटा मैंडिकल कॉलेज में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज देवेंदा ने बताया कि बालिका के शरीर पर करीब 20 घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में घाव हो गया, इसलिए श्वसन तंत्र को सुचारु रखने के लिए ट्यूब डाली गई है।

गए, जहां से बच्चों को कोटा रेफर किया गया है।

बालिका के दादा भंवरलाल सेन का कहना है कि वे लोग सीतापुरा रहते हैं। वहीं से बालिका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने तालेड़ा जाती थी, जहां पर यह घटना हुई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका को इतनी बुरी तरह काटा है कि उसके शरीर पर चरेरे को छोड़कर लगभग सभी जगह पर घाव हो गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में वे वैन से कई बार बच्चों को

लेने भी जाते हैं, तब बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स स्कूल में घूमते नजर आते हैं। उन्होंने कहा, सरकार तत्काल इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान ले। मेडिकल कॉलेज कोटा में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज का कहना है कि बालिका के शरीर पर करीब 2० के आसपास घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में भी घाव हो गया है। इसीलिए ट्यूब डाली गई है, ताकि बालिका के श्वसन तंत्र को सुचारु रखा जा सके।बालिका के हाथ, पैर और छाती सहित, कई जगह पर घाव के निशान हैं।

भारत में निपाह वायरस से पहली मौत

नई दिल्ली, 12 फरवरी। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित दो मरीजों में से एक मरीज की मौत हो गई है। देश में इस साल निपाह वायरस से यह पहली मौत है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि 11 नववरी 2०26 को पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट किए गए निपाह संक्रमण के दो

संक्रमित नर्सिंग स्टाफ नॉर्थ 24 पराना जिले के बारासात के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। इनमें एक पुरुष नर्स और एक महिला नर्स शामिल थीं। पुरुष नर्स इलाज के दौरान ठीक हो गया, लेकिन महिला को उपचार के दौरान मौत हो गई।

बांग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
महिलाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, वहीं प्रमुख दलों ने भी उन्हें केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक नामांकन दिए हैं। 2०26 के चुनाव महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्पष्ट और जबरदस्त गिरावट दर्शाते हैं और बांग्लादेश की राजनीति में लैंगिक समानता के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गुरुवार को चुनाव के दिन ढाका में भारी मतदान देखा गया, जहां जमात और बीएनपी के बीच मुकाबला चुनावी परिदृश्य को परिभाषित करता नजर आया। जनरेशन-ज़ैड आंदोलन के बाद हो रहे इस पहले चुनाव में जमात और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़पों की भी खबरें सामने आईं।

श्रीलंका के लिए हवाई उड़ानों के किराए में भारी वृद्धि

भारत-पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलम्बो में होने वाले मुकाबले के कारण यह वृद्धि हुई है

- बड़ी संख्या में लोग कोलम्बो जा रहे हैं इस वजह से चेन्नई से कोलम्बो की हवाई टिकट, जो 7,127 रुपए की होती थी, के दाम बढ़कर 22 से 25 हजार तक पहुँच गए हैं।

किराया सामान्यतः कम रहता है। इसी वजह से चेन्नई से श्रीलंका जाने वाले यात्रियों की संख्या आमतौर पर अधिक रहती है।

सामान्य दिनों में चेन्नई-श्रीलंका के बीच हवाई किराया लगभग 7,127 रुपये होता है, लेकिन 13 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास का किराया 22,073 रुपये से 25,2०7 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया

42,231 रुपये तक हो गया है। 14 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस का किराया 2०,7०8 रुपये से 25,2०7 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया 35,217 रुपये तक बढ़ गया है।मैच के दिन यानी, 15 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस में किराया 18,283 रुपये से 19,464 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस में 28,660 रुपये से 42,231 रुपये तक निर्धारित किया गया है।

हिंसा व हत्याओं के वातावरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के बीच वोटों के लिए मुकाबला हुआ। मतदान प्रक्रिया बीएनपी और जमात के समर्थकों के बीच झड़पों में हुई।

पहले, शेख हसीना के शासनकाल में बीएनपी और जमात ने चुनाव लड़ने के लिए आपस में गठजोड़ किया था। पर अब अवाामी लीग के मैदान में न होने से ये दोनों कट्टरपंथी दल अब एक-दूसरे से अलग हो गए हैं और सत्ता पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धी कर रहे हैं। जमात एक इस्लामी झुकाव वाला बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है।

भारत के लिए ये दोनों दल एक तरह से ‘‘हांक्सन चैंडस’’ प्रस्तुत करते हैं, अर्थात दोनों ही मूल रूप से भारत-विरोधी हैं और दोनों ने देश में बचे हुए हिंदुओं को बाहर निकालने की दिशा में काम किया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार मतदान की सफलता का दावा कर रही है और एक नई शुरुआत की आशा व्यक्त कर रही है।

^[1] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65०15/96, जयपुर कार्यालय: सुघर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : ०141-2373513, कोटा कार्यालय :- पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386०31, 2386032,फैक्स:०744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : ०294-2410146, बीकानेर कार्यालय :- कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स ०151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-2०1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: ०7469-230600 चूरू कार्यालय :- एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: ०1562-256908